स्मार्ट सिटी व वित्त आयोग के पैसों से होगा इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो का निर्माण

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के 14 शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में डिपो बनाने की अड़चन दूर कर ली गई है। डिपो बनाने के लिए पैसा न होने से बसें नहीं खरीदी जा रही थीं। अब लखनऊ समेत छह शहरों में स्मार्ट सिटी और पांच शहरों में 14वें व 15वें वित्त आयोग के पैसे से मेंटीनेंस डिपो बनाए जाएंगे। उच्चाधिकारियों की बैठक में इसपर सहमति बन गई है। जल्द ही इसपर काम शुरू होगा। शेष शहरों के लिए भी जल्द फैसला हो जाएगा।

नगर विकास विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक जल्द ही कार्यवाही शुरू की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के 14 शहरों में 700 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाई जानी हैं। हालांकि कुछ शहरों में बसों का संचालन शुरू भी हो गया है, लेकिन मेंटीनेंस डिपो न बनने से बसों की सफाई और

बजट की दिक्कत दूर, जल्द शुरू होगा डिपो का काम

मरम्मत में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने अब डिपो बनाने के लिए बजट की समस्या को दूर कर दिया है। स्मार्ट सिटी वाले सभी 6 शहरों में जहां स्मार्ट सिटी मिशन से डिपो बनाने के लिए धनराशि दी जाएगी, वहीं अन्य 8 शहरों में डिपो का निर्माण 14वें व 15वें वित्त आयोग द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। नगर विकास की ओर से जारी आदेश में कहा है कि मेंटीनेंस डिपो बनाने का काम जल निगम की निर्माण इकाई सीएंडडीएस को दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अनुबंध शर्तों के आधार पर निर्धारित समय के अंदर मेंटीनेंस डिपो बनाकर दिया जाना है, जिससे सभी 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलने लगें।

इन शहरों में चलनी हैं इलेक्ट्रिक बसें

प्रदेश के 14 शहरों में (6 स्मार्ट शहर और 8 अन्य शहरों में) इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया गया था। इनमें स्मार्ट सिटी मिशन केतहत चयनित 10 शहरों में से 6 शहर लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, बरेली, और झांसी को शामिल किया गया है। जबकि शेष 8 शहरों में अयोध्या, सीतापुर, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, गोरखपुर व मेरठ को शामिल किया गया है। इन सभी शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के साथ ही बसों के लिए मेंटीनेंस डिपो बनाने का फैसला किया गया था। लेकिन बजट न मिलने से डिपो बनाने का काम शुरू नहीं हो पा रहा था।